विनियोग संख्या 63 - भारत का उच्चतम न्यायालय
APPROPRIATION No. 63–SUPREME COURT OF INDIA

			कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
			(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
मूल	*Original*	*88,02,00*	*100,69,00*	*99,13,41*	*–1,55,59*
पूरक	*Supplementary*	*12,67,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*1,55,49*

टीका और टिप्पणियां

1. *विनियोग* में, कुल बचतें (*155.59 लाख रु.*) दिसंबर, 2009 और मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए *1267.00 लाख रु.* के पूरक *विनियोग* का 12 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 2 प्रतिशत थीं।

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2014"	Major Head "2014"				
न्याय प्रशासन	Administration of Justice				
मू.	*O.*	*8802.00*	*9913.51*	*9913.41*	*–0.10*
पू.	*S.*	*1267.00*			
पु.	*R.*	*–155.49*			

(I) "उच्चतम न्यायालय - स्थापना" के अंतर्गत *8802.00 लाख रु.* के मूल *विनियोग* को *1267.00 लाख रु.* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *10069.00 लाख रु.* कर दिया गया, तथापि, जो पेशेवर सेवाओं के लिए बिल प्राप्त न होने, वेतन एवं भत्तों का बकाया बिलों और सीसीटीवी लगाए जाने में विलंब होने की वजह से निर्णीत हर्जाने की वसूली और अन्य सुरक्षा उपस्करों के कारण *155.59 लाख रु.* की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

Notes and comments

1. In the *appropriation*, the overall savings (*Rs.155.59 lakhs*) constituted 12 percent of the supplementary *appropriation* of *Rs.1267.00 lakhs* obtained in December, 2009 and March, 2010 and 2 percent of the total sanctioned *appropriation.*

Saving occurred under the following major head:-

(I) Under "Supreme Court – Establishment" – the original *appropriation* of *Rs.8802.00 lakhs* was augmented to *Rs.10069.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *Rs.1267.00 lakhs* which, however, remained unutilised to the extent of *Rs.155.59 lakhs* - due to non-receipt of bills for professional services, arrear bills of pay & allowances and recovery of liquidated damages owing to delay in installation of CCTV and other security equipments.